give this partnership a people's orientation through greater cooperation on developmental issues and through joint efforts to promote a democratic international order.

पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद

177. **श्री ओंकार सिंह लखावतः**

श्री डब्लयू अड़ौ सिंहः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पडोसी देशों के साथ हमारे कितने अनिर्णीत भूमि और समुद्रीय सीमा विवाद है;

(ख) वे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ भू-भागीय क्षेत्राधिकार, हथियारों, विस्फोटकों और स्वापक पदार्थों की सीमा पार से तस्कीरी के संबंध में हमारे विवाद है; और

(ग) विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) पाकिस्तान

जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 78 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय प्रदेश पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। सिर क्रीक में भी, भारत और पाकिस्तान के सीमा के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं; और इसके अलावा, दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का अभी भी सीमांकन नहीं हुआ है।

सरकार भारत और पाकिस्तान के सभी आपसी मसलों का शिमला समझौता की रूपरेखा के भीतर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत पुनः आरम्भ हो गई है।

बंगलादेश तथा म्यामार

बंगलादेश और म्यांमार के साथ हमारी भू-सीमा के सीमांकन का कार्य अधूरा है। बंगलादेश का साथ हमारी समुद्री सीमा का मसला भी अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

चीन

जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथिक चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारतीय प्रदेश के लगभग 5,120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था।

भारत और चीन सीमा मसले के समाधान का कोई उचित, तर्क संगत और परस्पर रूप से स्वीकार्य हल निकालने की दिशा में कार्य करने के लिए बचनबद्ध है। दोनों देश सीमा मसले पर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) और भारत-चीन विशेष दल (ईजी) की रूपरेखा के अन्तर्गत बातचीत कर रहे है। सितम्बर, 1993 में संपन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने से संबद्ध करार तथा नवम्बर, 1996 में संपन्न सीमा क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने से संबद्ध करार सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने में योगदान करेंगे।

नेपाल और भूटान

भूटान के साथ हमारा कोई अनसूलझा सीमा विवाद नहीं है।

नेपाल साथ, सीमा के सीमांकन का कार्य चल रहा है। यह कार्य 1981 में इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त तकनीकी स्तर की सीमा समिति (जेटी एल सी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। जेटीएलसी के कार्य संचालित करने के दौरान, दोनों क्षेत्रों के छोटे खण्डों में सीमा को सीमांकित करने में कुछ कठिनाईयां आड़े आई है। ये खण्ड नारासाही सूषता और कालापानी है।

नारासाही-सूषता क्षेत्र में, नेपाल ने नदियों के मार्ग परिवर्तन की समस्या के कारण भूमि के एक भाग पर अतिकरण किया है। इस पर जेटीएलसी के तहत चर्चा हुई थी तथा किसी प्रकार का संयुक्त स्थल सत्यापन संचालित करने से पूर्व, इस क्षेत्रों को फोटोग्राफ सर्वेक्षण करने का फैसला किया था. कालापानी का मसला उत्तर-पश्चिमी नेपाल के निकट उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ जिले में लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित है। नेपाल इस पर अपना प्रदेश होने का दावा करता है और लिपु लेख को जाने वाले मार्ग पर कालापानी स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस चौकी को खाली करने के लिए कहता है। इस पर वह अपना दावा सुगोली की 1815 की संधि के आधार पर इस कारण से जताता है कि यह क्षेत्र काली नदी के पूर्व में अब स्थित है। इस क्षेत्र में सीमा की सीध वास्तविक रूप से सुपरिभाषित है। जिसका सीमांकन विगत शातब्दी में किया जा चुका है।

जून, 1997 में प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान, यह फैसला किया था कि जेटीएलसी का संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू सी) पश्चिमी सीमा के सीमांकन के मसले का हल निकालेगा जिसमें कालापानी क्षेत्र भी शामिल है। संयुक्त तकनीकी स्तरीय सीमा समिति और संयुक्त कार्यदल के इस मसले को अपने हाथ में ले लिया है।

हथियारों, विस्फोटकों और स्वापकों की सीमा पार तस्करीः

जहां तक उपरोक्त मसलों के संबंध में मतभेद का सवाल है, भारत के खिलाफ निर्दशित आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान का समर्थन जारी है, इस समर्थन में अन्य बातों के साथ-साथ, विस्फोटको, हथियारों, और स्वापकों की तस्करी शामिल है। सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्तालाप जारी रखे हुए है। यह समस्या अन्य पड़ोसी देशों की सीमाओं पर भी मौजूद है परन्तु इसका मुकाबला करने के संबंध में कोई मतभेद नहीं है।

भारत और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा तीर्थयात्राओं के लिए अनुमति

178. **श्री ओंकार सिंह लखावतः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(**क**) क्या भारत द्वारा पाकिस्तान तीर्थयात्रियों को अजमेर में स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर होने वाले सालाना उर्स और कुछ अन्य अवसरों पर आने की अनुमति प्रदान की जाती है;

(**ख**) क्या पाकिस्तान प्राधिकारियों द्वारा करोड़ों भारतीयों की ईष्ट देवी हिंगलाज और पाकिस्तान में स्थित अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को अनुमति दी गयी थी, यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किस-किस तारीख को कितन-कितने तीर्थयात्रियों को अनुमति प्रदान की गयी, और

(ग) क्या भारत सरकार भारतीय तीर्थ यात्रियों को हिंगलाज की यात्रा के लिए पाकिस्तान से अनुमति प्राप्त करने का कोई प्रयास कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) पवित्र धार्मिक स्थलों के यात्रा संबंधी भारत पाकिस्तान प्रोतांकोल 1974 के अन्तर्गत पाकिस्तान तीर्थयात्री भारत में अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सहित धार्मिक स्थलों की यात्रा करते है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन भारतीय तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या, जिन्होंने पाकिस्तान में विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की इस प्रकार हैः

अनसर/स्थान/माह	वर्ष	उन तीर्थयात्रियों की अनुमानित संख्या जिन्होंने यात्रा की
बेसाखी (अप्रैल)	1994	1920
	1995	1980
	1996	1925
गुरू अर्जुन देव जी का शहीद दिवस (मई)	1994	660
	1995	640
	1996	545
महाराज रंजीत सिंह जी की बरसी (नून)	1994	340
	1995	300
	1996	245
शादानी दरबार हयात पिताफी (अक्तूबर)	1994	170
	1995	180
	1996	190
गुरू नानक देव जी को जयन्ती (नवम्बर)	1994	2290
	1995	2110
	1996	2180

(घ) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से द्विपक्षीय प्रोतोकोल के अन्तर्गत भारत से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए हिंगलाज देवी मंदिर सहित और अधिक धार्मिक स्थलों को खोलने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताल का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

LIS Readiness to Introduce New Chapter in Indo-US Ties

179. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the US President has in his message of greeting on India's Golden Jubilee Anniversary, indicted that the US was ready to introduce a new chapter in its ties with India; and

(b) if so, what steps have since been taken bilaterally, unilaterally or otherwise to introduce such a new chapter in Indo-US ties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWANI): (a) Yes, Sir.